

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

ठब्बू०पी० (एस०) सं०-४५० वर्ष २०१७

बैंक ऑफ इंडिया, हजारीबाग शाखा, अपने सहायक महाप्रबंधक अतुल प्रताप सिंह, पुत्र—श्री उदय पाल सिंह, निवासी—जिला परिषद् भवन, जिला बोर्ड चौक, डाकघर एवं थाना—सदर, जिला—हजारीबाग (झारखण्ड) याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, डी०सी० कार्यालय, न्यायालय परिसर, डाकघर, थाना एवं जिला—हजारीबाग (झारखण्ड)
3. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, डी०एफ०ओ० कार्यालय, न्यू बस स्टैंड के पास, डाकघर, थाना एवं जिला—हजारीबाग (झारखण्ड)
4. आनंद मेहता, पुत्र—भैरो मेहता, निवासी ग्राम एवं डाकघर—पहड़ा, थाना—कटकमसांडी, जिला—हजारीबाग (झारखण्ड) उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ता के लिए :—श्री अवनीश रंजन, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :— एमडी० राजीव रंजन मिश्रा, अधिवक्ता

०४ / दिनांक: १२ अप्रैल, २०१८

याचिकाकर्ता बैंक ऑफ इंडिया है, जिसने प्रतिवादी संख्या २ और ३, जो उपायुक्त, हजारीबाग और वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग हैं, को निर्देश देने के लिए

प्रार्थना की है कि वे वाहन एच०जी०वी०-१ लोडर बैकहो जे०सी०बी० मशीन जिसका पंजीकरण सं०-जे०एच०-०१ ए०जी० 7703, इंजन सं० 41122630929190 और चेसिस सं०-एक्स 1382789 है, को बैंक के पक्ष में मुक्त करें न कि प्रतिवादी सं०-४ के पक्ष में।

इस मामले में तथ्य निर्विवाद है। प्रतिवादी सं०-४ ने याचिकाकर्ता बैंक से ऋण लेने के बाद एक जे०सी०बी० मशीन खरीदी। प्रतिवादी सं०-४ इस वाहन के साथ वन अपराध में शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप जे०सी०बी० को जब्त कर लिया गया था। कन्फीसकेशन केस सं०-०४ / 2012 में दिनांक 12.03.2013 को अंतिम आदेश पारित किया गया था, जिसके तहत यह आदेश दिया गया था कि वाहन को जब्त कर लिया जाना चाहिए। उक्त आदेश के खिलाफ अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रतिवादी सं०-४ द्वारा अपील दायर की गई है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि वन अपराध करने के लिए एक आपराधिक मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है। इस बिन्दु पर याचिकाकर्ता यानी बैंक, इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना करता है कि उत्तरदाताओं को प्रतिवादी सं०-४ के पक्ष में वाहन जारी न करने और बैंक के पक्ष में इसे जारी करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि वाहन बैंक का बंधक है।

पार्टियों को सुनने के बाद, मुझे लगता है कि जब्ती कार्यवाही में अंतिम आदेश पहले ही पारित कर दिया गया है और वाहनों को जब्त कर लिया गया है। चूंकि वाहन को पहले ही जब्त कर लिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता को या प्रतिवादी सं०-४ को वाहन जारी करने का काङ्क्षा सवाल ही नहीं है।

इस प्रकार, यह रिट एप्लिकेशन खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्यायालय)

